गए विकल्पों का वर्ष वार/श्रेणीवार ब्यौरा निम्नलिखित है :—

श्रेणी	1991–92	1992–93	1993–94 (4.3.94 तक)	कुल
कार्यपालक . . .	390	619	357	1366
पर्यवेक्षक . .	127	268	125	520
कामगार . . .	504	1149	636	2289
कुल :	1021	2036	1118	4175

उपर्युक्त के अतिरिक्त, वर्ष 1993–94 के बाकी बचे हुए समय में लगभग 600 कर्मचारियों के स्वैच्छिक सेवा-निवृत्ति लेने की आशा है ।

(घ) सरकार द्वारा स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति स्कीम के अंतर्गत उपलब्ध कराई गई निधियों की कुल धनराशि इस प्रकार है :—

(करोड़ रुपयों में)

1991–92	20.50
1992–93	41.00
1993–94	25.75
(यथा 1.3.94 को)	—
कुल .	87.25

(ङ) स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति स्कीम के लिए निधियां, सरकारी उपक्रमों द्वारा स्वीकार किए गए आवेदनों के लिए आवश्यक निधियों हेतु उनके विशेष अनुरोधों पर जारी की जाती हैं । हैवी इंजीनियरिंग कार्पोरेशन को और निधियां उनके अनुरोध प्राप्त होने पर जारी की जाएंगी ।

मध्य प्रदेश में खादी और ग्रामोद्योगों का विकास

3160. श्री अजीत जोगी :
श्री मूल चन्द मीणा :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1990–91 और 1991–92 के दौरान मध्य प्रदेश में खादी और ग्रामोद्योगों के विकास के लिए तैयार की गई योजनाओं और राज्यों में विभिन्न खादी और ग्रामोद्योग केन्द्रों को सरकार द्वारा उपलब्ध कराए गए अनुदान का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार ने वर्ष 1992–93 के दौरान अनुदान की राशि में वृद्धि की थी;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) गुजरात और देश के अन्य राज्यों में खादी को लोकप्रिय बनाने के लिए क्या कदम उठाए गये हैं अथवा उठाने का विचार है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम. अरूणाचलम) : (क) खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग, मध्य प्रदेश में खादी तथा ग्रामोद्योगों के लिए योजनाओं का कार्यान्वयन करता है। कार्यान्वयन के लिए मुख्य रूप से निम्नलिखित ग्रामो-

योगों को प्रोत्साहन दिया जा रहा है। कुटीर कुम्भकारी, चूना बनाना, अगरबत्ती बनाना, हस्त निर्मित कागज, लाख, बॉस और बेंत, मधुमक्खी पालन, घानी तेल, गुड़ और खॉडसारी इत्यादि। वर्ष 1990–91 और 1991–92 के दौरान दिये गये अनुदानों और ऋणों का विवरण इस प्रकार है :

(रु० करोड़ में)

वर्ष	खादी		ग्रामोद्योग	
	अनुदान	ऋण	अनुदान	ऋण
1990–91 . . .	0.81	1.58	0.05	0.99
1991–92 . . .	1.49	0.93	0.43	3.70

(ख) जी, हां। (ग) ब्यौरे इस प्रकार हैं :

(रु० करोड़ में)

वर्ष	खादी		ग्रामोद्योग	
	अनुदान	ऋण	अनुदान	ऋण
1992–93 . . .	1.76	3.38	0.56	2.06

(घ) खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग ने गुजरात और अन्य राज्यों में खादी को लोकप्रिय बनाने के लिए निम्नलिखित कई उपायाय किये है :

1. सूती खादी की किस्म को बेहतर बनाने और इसका उत्पादन बढ़ाने के लिए खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग ने उच्च गति के छः तकुओं वाल नये मॉडल के चरखों और ग्रामलक्ष्मी करघों का प्रचलन आरंभ किया हें ।

2. कताईकारों को अच्छी किस्म का कच्चा माल नियमित रूप से मिलता रहे इस बात को सुनिश्चित करने के लिए देश के विभिन्न भागों में केन्द्रीय स्लाइवर संयंत्र स्थापित किये जा रहे हैं।

3. नये मॉडल के चरखों के पुर्जों भण्डारण और उनकी आपूर्ति करने के लिए देश के विभिन्न भागों में प्रबंध किये जा रहे है ताकि चरखे निष्क्रय न रहें।

4. रंगाई और छपाई के मानकीकरण की प्रक्रिया पर ध्यान दिय जा रहा है ।

5. आयातित मेरीन बूल का प्रतिस्थापन एक्रेलिक फाइबर से करने के लिए उसका उत्पादन आई पी सी एल के सहयोग से आरंभ किया जा चुका है।

किये गये उपर्युक्त उपायों के अलावा निम्नलिखित कार्य भी करने का प्रस्ताव है :

(क) खादी उत्पादन विकास केन्द्र

ख) परिधान उत्पादन केन्द्र

(ग) खादी निर्यातोन्मुख एकक।

सौराष्ट्र में उद्योग लगाने के लिये अनिवासी भारतीयों से प्राप्त प्रस्ताव

3161. **श्री चिमन भाई हरिभाई शुक्ल :**

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान सरकार को गुजरात के सौराष्ट्र क्षेत्र में उद्योग स्थापित करने के लिये अनिवासी भारतीयों से कितने प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं;

(ख) इन प्रस्तावों पर सरकार द्वारा अब तक क्या कार्यवाही की गई है और इन प्रस्तावों में प्रमुख उद्योग कौन-कौन से हैं जिन्हे सौराष्ट्र क्षेत्र में स्थापित करने के लिये अनुमति मांगी गई है; और

(ग) सरकार द्वारा अब तक कितने प्रस्तावों को स्वीकृति प्रदान कर दी गई है और शेष प्रस्तावों को कब तक स्वीकृति प्रदान कर दिये जाने की संभावना है तथा इस संबंध में ब्यौरा क्या है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा साही) : (क) से (ग) गुजरात के सौराष्ट्र क्षेत्र में विभिन्न क्षेत्रों अर्थात् कनफैक्शनरी (चाकलेट, टॉफी और च्यूइंग गम को छोड़कर), खुम्बी और स्क्रैप की रीसाइकिलिंग के क्षेत्र में उद्योगों की स्थापनार्थ सरकार ने पिछले तीन वर्षों 1991 से 1993 के दौरान तीन प्रस्ताव अनुमोदित किये हैं जिनमें अप्रवासी भारतीयों का 71.25 लाख रुपये का निवेश अंतर्ग्रस्त है। कोई भी प्रस्ताव लम्बित नहीं है।

Setting up of heavy industries in Haryana

3162. SHRI S. S. SURJEWALA: Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) what type of heavy industries have been set up in the Public Sector in the State of Haryana after its inception;

(b) whether Haryana is being discriminated against in the matter of allocation/setting up Public Sector Heavy Industries;

(c) whether it is also a fact that the project to set up Rail Coach Factory has been shelved and the same was set up in neighbouring State under political pressure; and :

(d) whether Government propose to set up any other heavy industries in Haryana besides the Karnal Refinery to compensate the States?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF INDUSTRY (SMT. KRISHNA SAHI): (a) One Central Public Sector Undertaking namely Indian Drug and Pharmaceuticals Ltd., is in operation since 1961 in Haryana. Besides there are two units of Central Public Sector in Haryana, one unit of HMT in Pinjore and another of Cement Corpn., of India in Bhiwani.

(b) No, Sir. Setting up of new public sector undertaking/projects or expansion of existing units are decided keeping in view the techno-economic feasibility of the projects and availability of resources, together with balanced regional development of the country.